Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 25-08-2006

Participants : Singh Shri Bijendra

an>

Title : Alleged misuse of Central funds by States allocated for various schemes.

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) : महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया।

मान्यवर, इस देश में एक वैधानिक व्यवस्था है कि भारत सरकार व राज्य सरकार बहुत सी जनहितकारी विकास योजनाओं से देश में विकास करती है। मैं यूपीए सरकार, माननीया सोनिया जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने स्वर्गीय राजीव जी के सपनों को पूरा करने के लिए इस देश में सर्वांगीण विकास के लिए, पंचायतीराज के साथ-साथ हर गांव को बिजली, हर गांव में सड़क निर्माण के लिए राजीव गांधी विद्युतीकरण व महानगरों की विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एपीडीआरपी स्कीम को स्वीकृत किया है।

मान्यवर, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आज तक इन योजनाओं में उ0 प्र0 को 32 सौ करोड़ रूपए स्वीकृत कर 2161 करोड़ रूपए आवंटित किए गये हैं। यह राशि मूल रूप से जनता का पैसा है और जनता के लिए है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य व धनराशि को केंद्रीय कार्यसमिति द्वारा निविदा अनुमोदित धनराशि को आर.ई.सी. के रेटों से लगभग 60 प्रतिशत बढ़ाकर मनमानी दरों पर विभिन्न प्राइवेट कंपनियों से कराया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर एटा में 39 करोड़ रूपए स्वीकृत धनराशि को अनुमोदित कर 64 करोड़ 26 लाख किया गया है,

---

*The speech was laid on the Table.

जिसका टेंडर मैसर्स (एक्यूरेट ट्रांसफार्मर दिल्ली) व आगरा, अलीगढ़, हाथरस व मथुरा में स्वीकृत धनराशि 49 करोड़ 14 लाख को बढ़ाकर 84 करोड़ 85 लाख रूपए अनुमोदन उपरांत (मैसर्स रिलायंस इनर्जी लिमिटेड, नोएडा) फिरोजाबाद व मैनपुरी, फरूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरय्या, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कानपुर नगर एवं कानपुर देहात जनपदों की स्वीकृत धनराशि को अनुमोदित कर हजारों करोड़ रूपयों में बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं विभिन्न प्राइवेट कंपनियों द्वारा अनएप्रूव्ड कंपनियों का मैटेरियल लगाया जा रहा है, जिसमें कोई गुणवत्ता नहीं है और इससे विद्युतीकरण को कोई लाभ नहीं मिलेगा।

महोदय, इसी तरह उ0 प्र0 के विभिन्न महानगरों में विद्युत व्यवस्था को सुचारू तथा मजबूत किए जाने हेतु एपीडीआरपी स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार ने उ0 प्र0 सरकार को 1091 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। जिसमें से मेरे महानगर अलीगढ़ को 30 करोड़ रूपए स्वीकृत किये गये हैं। लेकिन इस धनराशि को अधिकारियों ने बंदरबाट कर बर्बाद कर दिया है। क्योंकि अधिकारियों ने लोकल कांट्रैक्टरों से लोकल मैटेरियल लगवाकर अनुचित भुगतान कर दिया है। जो पूरे प्रदेश में किया गया है। इस कार्य को हुए मात्र एक वर्ा ही हुआ है और सभी ट्रांसफार्मर जल चुके हैं व तारों का टूटना शुरू हो चुका है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उ0 प्र0 सरकार विकास कार्यों के प्रति जागरूक नहीं है।

महोदय, मैं इस योजना के अंतर्गत पीएमजीएसवाई योजना की दुर्दशा की तरफ भारत सरकार का ध्यान आकर्ति कराना चाहता हूं। इस योजना के अंतर्गत आज तक उ0 प्र0 सरकार को दो हजार नौ सौ करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। जिसमें से 2222 करोड़ रूपए आवंटित किए जा चुके हैं। लेकिन उ0 प्र0 सरकार ने केवल 1366 करोड़ रूपए खर्च किए हैं और

आज उ0 प्र0 सरकार के पास भारत सरकार का 856 करोड़ रूपए शेा हैं। जिसकी स्वीकृत धनराशि से 19700 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना था, लेकिन उ0 प्र0 सरकार 1300 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर पायी। आज भी 6700 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य शेा है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य कुशलता का प्रमाण है।

महोदय, जनपद अलीगढ़ में यमुना नदी के बाढ़ नियंत्रण हेतु बंधा निर्माण के लिए 80 करोड़ रूपए स्वीकृत कर लगभग 48 करोड़ रूपए आवंटित किए गए, लेकिन उ0 प्र0 के सिंचाई विभाग ने उक्त धनराशि को भ्रटतम अधिकारियों के माध्यम से अपने मनचाहे ठेकेदारों को देकर सफाया कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास कार्यों के लिए कोसते हैं और माननीय सोनिया जी एवं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं। जबकि गत र्वा प्रदेश की योजना हेतु 11 हजार करोड़ रूपए की मांग के उपरांत उसे 13 हजार करोड़ रूपए दिए गए।

महोदय, प्रदेश की विभिन्न विकास कार्य योजनाओं में 75 प्रतिशत भारत सरकार का धन है। जिसमें पंचायती राज में, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायतें, ग्राम पंचायतें, एसजेआरवाई, इन्दिरा आवास, राशन प्रणाली, मिडडे मील, सतत शिक्षा, सुनिश्चित रोजगार योजना आदि वे योजनाएं हैं, जो भारत सरकार की देन हैं।

अंत में महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन विभिन्न योजनाओं में जनता के धन के दुरूपयोग को रोका जाए और विद्युत विभाग व ग्राम विकास विभाग से स्पेशल टीमों का चयन कर तत्काल जांच कराने के निर्देश दिए जाएं, जिससे कि भारत सरकार की इच्छा के अनुरूप जनता को विकास कार्यों का लाभ मिल सके। जयहिंद।